भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3726
18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण और आर्थिक जनगणना के प्रकाशन में विलंब

3726. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्राथमिक डेटा तैयार करने की समय सारिणी का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण और आर्थिक जनगणना के प्रकाशन में विलंब हो रहा है, और मासिक मुद्रास्फीति रीडिंग तथा जीडीपी डेटा प्रभावित हो रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपयोगकर्ताओं की ओर से डेटा की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राथमिक डेटा तैयार करने की समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना और डेटा की गुणवत्ता को प्रामाणिक और संदेह रहित रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा घरेलू उपभोग व्यय (एचसीईएस: 2022-23) पर नवीनतम सर्वेक्षण अगस्त, 2022 माह - जुलाई, 2023 माह के दौरान आयोजित किया गया था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष फरवरी, 2024 माह में फैक्टशीट के रूप में प्रकाशित किए गए थे। एचसीईएस 2022-23 की रिपोर्ट जून 2024 में जारी की गई है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नियमित अंतराल पर आर्थिक जनगणना भी करता है। पिछली अर्थात् सातवीं आर्थिक जनगणना का क्षेत्रकार्य 2019-21 के दौरान किया गया था । चूंकि यह अवधि कोविड-19 महामारी से प्रभावित थी और अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे, इसलिए 7वीं आर्थिक जनगणना के आंकड़ों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

(ख) और (ग): आंकड़ों की गुणवत्ता के बारे में उपयोगकर्ताओं से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि द्वारा भारत में विभिन्न प्रमुख संकेतकों के आधिकारिक डेटा स्रोत के रूप में किया जाता है। हालांकि, सांख्यिकी और कार्यक्रम

कार्यान्वयन मंत्रालय, देश में सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते, डेटा गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है। इसे प्राप्त करने के लिए, विभिन्न सांख्यिकीय उत्पादों में सशक्त और सुपरिभाषित तंत्रों को नियोजित किया जाता हैं, जिनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बदलती जरूरतों, प्रतिक्रिया और कार्यप्रणाली में प्रगति के आधार पर समय-समय पर सुधार किए जाते हैं। डेटा संग्रह के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन-बिल्ट सत्यापन तंत्र के साथ कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) या वेब-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्राथमिक डेटा संग्रह किया जा रहा है। डेटा की सटीकता बहु-स्तरीय डेटा जांच और सत्यापन जांच द्वारा सुनिश्चित की जाती है। संकलात्मक प्रश्नों का समाधान करने और डेटा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण तंत्र का पालन किया जाता है। डेटा उपयोगकर्ताओं/हितधारकों के साथ नियमित संवाद भी आयोजित किए जाते हैं ताकि उनकी प्रतिक्रिया को शामिल किया जा सके और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे डेटा के बारे में उनकी समझ को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अग्रिम रिलीज कैलेंडर 2024-25 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों की रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही हैं।

*****